Report of National Minority Commission on the misuse of TADA

1932. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the National Minority Commission submitted Many report on the misuse of TADA or Minorities; and

(b) if so, what are its findings on the misuse of TADA on the Minorities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU: (a) and (b) The National Commission for Minorities has not submitted any Report under Section 9 (1) (h) of the National Commission for Minorities Act, 1992 on the misuse of TADA on minorities. However, the Commission has adopted a resolution in its meeting held on 6th June, 1994 recommending to the Government that it may consider immediate repeal of TADA.

Reports submitted by National Minorities Commission

1933. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) how many reports have been submitted by National Minorities Commission after it acquired the status of a statutory Commission;

(b) what are its recommendations;

(c) how many of the recommendations have been accepted; and

(d) the action initiated on the accepted recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU: (a) to (d) The National Commission for Minorities, set up under the National Commission or Minorities Act 1992 has not submitted any Report under Section 9 (1) (h) of the Act for its Annual Report under Section 12 thereof. However, it has submitted the Fourteenth Report pertaining to the period from 1.4.1991 to 31.3.1992 on behalf of the erstwhile Minorities Commission. The report is under examination.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निधियां

1934. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन राज्य सरकारों को दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त निधि को खर्च करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि किसी विशिष्ट शीर्ष के लिए उद्दिष्ट निधि को उस शीर्ष पर खर्च कर दिया जाता है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० तंग्काबालू) :(क) ब्यौरा संलग्न अनुपत्र में दिया गया है [**देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं०–43**]

(ख) विशिष्ट केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) किसी विशेष शीर्ष से पुनर्नियोजन के माध्यम को छोड़कर, यदि उसमें बचत है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निधियों का विपणन नहीं किया जा सकता।